

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2004—माघ 3, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 2-44/2003/1-8.—श्री अमन कुमार सिंह, भारतीय राजस्व सेवा, उपायुक्त (उत्पाद, नोएडा), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की सेवायें राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अमन कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जायेंगी.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988), आयुक्त, कोष एवं लेखा, को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है।

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (1984), आयुक्त, आदिमजाति कल्याण एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी एवं वित्त विकास निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव।

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक 95/2065/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री सी. के. खेतान, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 30-12-2003 से 6-1-2004 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।
5. श्री सी. के. खेतान, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री पी. सी. दलेई, पदेन सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे।

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक 97/2174/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री आर. पी. मंडल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 30-11-2003 से 6-12-2003 तक (7 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 7-12-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. मंडल, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री आर. पी. मंडल, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. मंडल, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

HOME DEPARTMENT
Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

Raipur, the 3rd January 2004

No. F-4-6-2004/Home-C.—In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the State Government of Chhattisgarh gives consent to extension of powers and jurisdiction to the whole of Chhattisgarh to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate and inquire into the offence No. 104/2003 registered under sections 302, 120 B, 427, 34 of Indian Penal Code read with sections 25, 27 Arms Act and any other offence(s) in connection with the said case.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. BAGAI, Principal Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2004

शक्र

क्रमांक 3/खाद्य/2004/29.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र./ई-1-5/03/एफ/2, रायपुर दिनांक 31-12-2003 के अनुक्रम में श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) पंजीयक सहकारी संस्थाएं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ एतद्वारा श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (1984) के स्थान पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2004

क्रमांक 20/डी-4556/21-ब/छ. ग./2003.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39 सन् 1987) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीपति की सहमति से तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1227/डी-366/21-ब/छ. ग./2003 दिनांक 11-2-2003 एवं अधिसूचना क्रमांक 4627/डी-534/21-ब/छ. ग./

2003 दिनांक 10-7-2003 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा एक प्राधिकरण का गठन करती है जो निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा.

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (2)	राजस्व जिलों के लिए (3)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	(1) बस्तर (2) उत्तर बस्तर कंकर
2.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	(1) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
3.	बिलासपुर	(1) बिलासपुर (2) जांजगीर-चांपा (3) कोरबा
4.	दुर्ग	(1) दुर्ग
5.	रायगढ़	(1) रायगढ़
6.	जशपुर	(1) जशपुर
7.	रायपुर	(1) रायपुर (2) धमतरी (3) महासमुंद
8.	राजनांदगांव	(1) राजनांदगांव (2) कबीरधाम
9.	सरगुजा (अंबिकापुर)	(1) सरगुजा (अंबिकापुर) (2) कोरिया

Raipur, the 2nd January 2004

No. 20/D-4556/XXI-B/C.G./2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987) and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh and in supersession of the previous Notification No. 1227/D-366/XXI-B/C.G./2003, dated 11-2-2003 and Notification No. 4627/D-534/XXI-B/C.G./2003, dated 10-7-2003, the State Government hereby constitute an authority known as District Legal Service Authority as the following schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	District Legal Services Authority (2)	For the Revenue Districts of (3)
1.	Bastar (Jagdalpur)	(1) Bastar (2) Uttar Bastar Kanker

(1)	(2)	(3)
2.	South Bastar (Dantewada)	(1) Dakshin Bastar Dantewada
3.	Bilaspur	(1) Bilaspur (2) Janjgir-Champa (3) Korba
4.	Durg	(1) Durg
5.	Raigarh	(1) Raigarh
6.	Jashpur	(1) Jashpur
7.	Raipur	(1) Raipur (2) Dhamtari (3) Mahasamund
8.	Rajnandgaon	(1) Rajnandgaon (2) Kabirdham
9.	Surguja (Ambikapur)	(1) Surguja (Ambikapur) (2) Korla

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73/118/03/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो “आई. आई. एल. एम. यूनिवर्सिटी, रायपुर” कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्वारा “आई. आई. एल. एम. यूनिवर्सिटी, रायपुर” को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 14th August 2003

No. F-73/118/03/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Vinियामन) Adhinyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "IILM UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "IILM UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

(b)

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-81/2003/उ.शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 (3) के अधीन मोदी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर के कुलपति द्वारा धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत अध्यादेशों को सहमति प्रदान करती है तथा छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 27 की उपधारा (4) द्वारा 5 (पांच) "प्रथम अध्यादेशों" को अनुमोदित करती है।

ये अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. सी. सिन्हा, सचिव.

ORDINANCE NO. – 1**Admission of Students of the University and their enrolment
(Section 27 (1) (a) of the Adhiniyam)**

- 1 In this Ordinance unless there is anything contrary to Statute and the Adhiniyam
- (a) "Qualifying examination" means an examination the passing of which makes students eligible for admission to a particular course of study leading to a Bachelors, Masters, M.Phil., Doctorate, Degrees, Diplomas or Certificates conferrable by the University.
- (b) 'Compartment' or 'Supplementary' means a result in which a student has been declared fail in ONE subject by the concerned examining body i.e. a recognized Board of Secondary Education e.g. CBSE, ICSE, State Board of Secondary Education, etc. Such a student may be declared pass if he/she secures required percentage of marks in the examination held subsequently by the same examining body and declared Pass.
- (c) "Equivalent examination" means an examination conducted by
- (i) Any recognized Board of Secondary Education or
- (ii) Any Indian or Foreign University or awarding body recognized by this University.
- (d) 'Gap period' means the period between the last date of attending the educational institution (excluding coaching institutes) and the date of taking the admission in the University.
2. The student seeking admission to the Pass/Hons. Degree/ Diploma courses of the University or schools/college institutes recognized and/or affiliated to the University and the Study Centres shall submit the application on prescribed form on or before last of submission of such form, along with necessary certificates.
3. The admission committee will screen the applications and eligible candidates will be awarded provisional admission. An entrance test for admission may be prescribed for certain courses by the Academic Council.
4. Admission will be offered on rolling basis in an academic year as prescribed by the Academic Council.
5. The Student shall within a month of his admission submit certified copies of :
- i. Character certificate from the Principal of the School/ College last attended
- ii. Evidence of the Date of Birth
- iii. Statement of marks of the qualifying examinations
- iv. Medical certificate certifying physical fitness
- v. Transfer Certificate and Migration certificate, wherever applicable.

- vi. Any other document which may be felt as necessary to grant admission or to evidence any fact declared.

The admission is subject to the submission of these certified documents. If any of these are found to be forged, tampered or false, the student's admission will automatically stand cancelled.

6. A student who has passed a part of any degree or diploma from another University/ awarding body shall be admitted to subsequent higher class for such examination in any institution / centre after its equivalence has been determined by the Academic Council.

7. A student with "Compartment/ Supplementary" result may be granted 'Provisional' admission to any of the courses of study to which he / she would have otherwise normally been admitted if he / she had secured clear pass grades.

Provided that a provisionally admitted student submits the statement of marks after passing in the qualifying examination before declaration of the semester result. In that case his/her result will not be withheld.

Provided that a student admitted student provisionally fails to pass in the qualifying examination, his/her admission shall be terminated irrespective of the results in the University examination and the fee paid shall not be refunded.

8. A student who desires to be admitted after a gap period of one year or more shall along with his application for admission submit an affidavit duly notarized, justifying the reasons of gap period and certifying that he/she had not taken admission in any other college and had not been rusticated or had not been sentenced to jail for a criminal offence or any other fact disqualifying him from taking admission.

9. A person who is under sentence of rustication or has been disqualified from appearing in an examination by any other University/Institution will not be admitted to any course of study in this University and its institutions / centers during the period of rustication or disqualification.

10. The admission of the students shall be completed within a month of commencement of each course every year or the date decided by the Academic Council.

Provided that where the dates specified or the dates decided by the Academic Council as the last date of admission happens to be a holiday, the next working day will be the last day of admission.

Provided further that the Vice-Chancellor shall have the powers to grant admission in cases of genuine hardship beyond the last date of admission as given above on the clear understanding that the attendance of all such students shall be counted from the date of commencement of the course.

11. The Student shall get automatically enrolled as a member of the University as soon as he / she is admitted and pays all the dues together with the prescribed fee for enrolment and submits migration certificate, wherever required.

ORDINANCE NO. – 2

Course of study to be laid for all degrees, diplomas and certificates
(Section 27 (I) (b) of the Adhiniyam)

1. There shall be a 'Board of Study' for every course or group of courses as decided by the Academic Council.
2. Each Board shall consist of the following members nominated by the Vice-Chancellor –
 - i. Professors of University Teaching Departments and Schools of Studies or Institutes in subjects for which it is constituted.
 - ii. Two Heads of College Departments from the Colleges, Study Centers teaching the said subjects up to the postgraduate/ degree level, to be nominated by the Vice Chancellor by rotation
 - iii. One Reader from the University Teaching Department and School of Studies teaching the said subjects to be nominated by the Vice Chancellor by rotation according to seniority,
 - iv. Not more than two teachers in the said subject to be nominated by the Vice Chancellor.
 - v. Five members to be co-opted, four of whom shall be experts from outside the University, and shall be from a recognized teaching research Institute or corporate experts in the subject under the faculty for which the Board is constituted.
3. The Chairman of the Board of Studies shall be nominated by the Vice Chancellor from amongst the members of the board referred to in subsection (2) above.
4. The term of the board of studies shall be two years
5. Pending the constitution of Board of Studies, the Vice Chancellor by an order can change the subject or subjects from one faculty to another and can perform other functions vested in the board of studies.
6. Besides that, as the need may be, the Vice Chancellor can constitute a Provisional Board of Studies and assign a new subject in the faculty, which may be popular and in demand in other states and Universities in order to benefit the students of this University.

Note: The Designation Professor, Reader, Lecturer is synonymous with Professor, Reader/ Associate Professor, Lecturer/ Assistant Professor.
The Board shall be constituted by the Vice Chancellor based on need and requirement of the University.

7. The curriculum shall be forward looking, student centric and shall be so framed that it clearly lays down the 'learning outcomes', which every student must attain. It shall focus on imparting not only the knowledge and concepts but skills and competencies too. Adequate application oriented exercises and live projects shall constitute the syllabus.
8. It shall identify the text/ reference books, journals, websites, CD-ROMS, case history, etc. which will enhance the learning standards of the student.
9. The academic Council shall lay down the subjects that a student shall study leading to the award of certificates, diplomas and degrees by the University.

ORDINANCE NO. -3

The Award of Degrees, Diplomas, Certificates and Other Academic Distinctions (Section (27)(I) (c) of the Adhiniyam)

1. The candidate after passing the examination prescribed for a particular certificate, diploma or degree shall become eligible for the award of said certificate, diploma or degree respectively, as the case may be.
2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of Certificate, Diploma or Degree before the Academic Council soon after the declaration of the results. On being approved by the Academic Council, the Certificate and Diplomas shall be issued to the respective candidates by the Registrar.
3. The Certificates and Diplomas shall be signed by the Registrar.
4. The approval accorded by the Academic Council for the award of the respective degrees shall be placed before the Board of Management for its concurrence. On being concurred by the Board of Management, the Degree shall be awarded to the successful candidates at the convocation.

Provided that if the candidate is in urgent need of the degree and the convocation is likely to be delayed, the degree may be given to him/her by the Vice-Chancellor on the payment of fee as may be prescribed by the University from time to time.

5. Degrees will have the same nomenclature as of UGC but University will be empowered to grant Diplomas of its own nomenclature.
6. The nomenclature of the programs that would be conferred by the University under different Colleges/ Schools shall be in following streams :-
 - i. Information Technology
 - ii. Nursing
 - iii. Science (including Bio-technology)
 - iv. Education
 - v. Engineering & Technology
 - vi. Medical Science
 - vii. Commerce/ Management/ Insurance
 - viii. Arts (including language)

The degrees-masters/ bachelors or diplomas shall be awarded for completion of the courses.

The Programs may get further bifurcated on the basis of sub streams and majors.

7. The University may establish as many additional schools and colleges imparting educating in specified fields as may be necessary to meet the requirements emerging through new areas of studies.
8. The programs/ courses in which approval of specific regulatory body or council is required will be offered after getting such approval/ permission.
9. The programs may be offered either by physical mode or in correspondence/ distant learning.

ORDINANCE NO. 4

The Conditions of The Award of Fellowships and Scholarships (Section 27 (1) (d) of the Adhiniyam)

- 1) Every year the University shall invite application through notifications for the awards to be made for Fellowships, Scholarships and students Scholarships.
- 2) Subject to the general conditions applicable to all Fellowships and Research Scholarships as laid down in paragraph 4 below, the value, duration and conditions for the award of University Grants Commission Fellowships shall be such as are laid down by the University Grants Commission.
- 3) The value and duration of Scholarships/Fellowships Instituted by the University shall be laid down by the Academic Council and approved by the Board of Management. The Selection of the candidate shall be made in accordance with the regulations laid down by the Board of Management from time to time.
- 4) Graduate and Postgraduate scholarships instituted by the University shall ordinarily be tenable for two academic sessions i.e. twelve months in the first year and ten months in the second year on condition that the scholarship holder produces a certificate of efficiency in studies from the Head of the Department in the subject of study.
- 5) The scholarship shall be tenable from the date on which the candidate joins the course or from the date specified to him in the award letter.
- 6) A scholarship shall be withdrawn in the subsequent year if the scholarship holder fails to secure at least 70% marks in the previous examination of the concerned course.
- 7) If a scholarship- holder is unable to appear at the previous examination on account of sickness or any other reasonable cause, the student shall be paid only if the Head of the Institution certifies that the scholar diligently studied for the examination but was unable to take the examination for reasons beyond control. Such a student shall not receive scholarship during the next session but shall be entitled to the scholarship for the subsequent year if the scholar passes the previous examination with the requisite standard in the succeeding year in the first attempt.

- 8) A scholarship – holder shall at all times be of good behaviour and observe all rules of discipline.
- 9) (A) A Scholarship shall be liable to termination, if-
- i. The scholarship-holder discontinues studies during the middle of the session.
 - ii. The scholarship-holder after he has been given a reasonable opportunity to explain his conduct is in the opinion of the Academic Council guilty of a breach of para 8 of this ordinance and if the Academic Council so directs, the scholarship-holder shall also be liable to refund the amount of scholarship drawn by him.
- (B) The order of termination passed by the Academic Council shall be final.

ORDINANCE NO. -- 5

Conduct of Examination (Section 27 (1) (c) of the Adhiniyam)

Definitions

University Student means a student enrolled in any college/school of the University, enrolled in any college/school recognized and affiliated to the University, admitted to Distance Education Centres and Study Centres, etc. of the University.

Regular Candidate means a student who has pursued the course of study in a school/ college and seeks to take examination of the University as such.

Methods of Computing the Attendance-

- a) Attendance at lectures delivered and practicals / clinicals / sessions if any, held during the academic session shall be counted.
 - b) Attendance at N.C.C./ N.S.S. Camp, outdoor assignments, etc. during the session shall be taken as full attendance at lectures / practicals on each such day of the camp and / or assignments and the days of journey to such camp/assignments.
 - c) Participation as a member of the University team in any Inter University competition shall be taken as full attendance for the day of participation in such competition.
 - d) For special reasons such as prolonged illness, deficiency in percentage of attendance not exceeding fifteen percent of the total number of lectures delivered and practicals/ clinicals / sessionals held in each subject can be condoned in writing by the Vice –Chancellor.
1. The students evaluation for award of all degrees/diplomas/certificates comprises the following.

(a) Assignments

(b) Examination

2. The weightage for the foregoing shall be as prescribed for each discipline and approved by the Academic Council.

3. Assignments

- a) The issue, submission and evaluation of assignments will be the responsibility of the Deans of respective colleges/schools. He shall maintain complete honesty in preparation and evaluation of the assignments.
- b) The entire class shall be divided in study groups.
- c) Each study group will be given a separate assignment.
- d) Minimum assignments per subject per semester to be given to the students shall be decided by Academic Council.
- e) Each student will be required to defend his assignment after submission through a process of presentation/viva-voce etc.
- f) Assignments will be prepared as per a standard format, approved by the Academic Council from time to time specific to colleges and schools.
- g) Students will be required to submit the assignments within two weeks from the date of issue/ any other time frame specified by the lecturer.
- h) Assignments submitted after the due date will not be assessed for more than 50% marks.

4. Examination

- a) The examination shall be the responsibility of the Dean of respective College/School. He shall maintain total academic honesty in the conduct of these examinations.
- b) The examination shall be held completion of formal teaching.
- c) The practical examinations, where applicable, shall be held and be given a weightage as per the directions of the Academic Council.

5. Results of Assignment and Examination

The result of assignments and examination shall be submitted to the Controller of Examinations for evaluation.

6. Arrangement of Examination

All arrangements for the conduct of examination shall be made by the Controller of Examinations (sub-Registrar Evaluation) in accordance with

such directions as may be issued by the Board of Management in consultation with the Academic Council.

7. The Controller of Examinations shall finalise the date of examination.
8. The Board of Management shall determine in consultation with the Academic Council about examination.
9. The University may change the examination centre of the examination any time if it deems proper without assigning any reason.
10. The Controller of Examination may on the recommendation of the Centre Superintendent appoint an amanuensis to write down dictation pertaining to answers to questions during an examination on behalf of an examinee who is unable to write himself/herself if he/ she is medically handicapped and possess a certificate of a Government Medical Officer, provided that such an amanuensis shall be a man/woman possessing qualification of at least one class lower than that of the examinee concerned.
11. The University may from time to time appoint Inspectors or Board of Inspectors to see that the examinations are conducted strictly in accordance with rules and procedures lay down. In the event of the Inspector pointing out a breach of rules or procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be necessary including postponement or cancellation, wholly or in part of the examination at the centre, and if any such action is taken a report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.
12. The Vice-Chancellor may cancel an examination at all/ any centers if he is satisfied that there has been leakage of question papers or any other irregularity which in his opinion warrants such a step and report the action taken at the next meeting of Board of Management.
13. The Board of Management in consultation with the Academic Council may issue such general instruction for the guidance of the Examiners, Centre Superintendents, Tabulators, Collators as it considers necessary for the proper discharge of their duties.
14. If a candidate has any communication to make on the subject of his/ her examination paper, it shall be made in writing to the Controller of Examination directly.
15. Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his/her examination, the matter shall be reported to

the Controller of Examination who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.

16. Except as otherwise decided by the Board of Management, the examination answer-books and the foil and counter foil of the marks obtained by the examinees except the tabulated results, shall be destroyed or otherwise disposed of after 6 months from the date of the declaration of the results of the examination provided that the evaluated answer books of revaluation shall be destroyed/disposed of only after 3 months of the declaration of the revaluation result.
17. The Controller of Examination shall publish the combined results of the University examination on the notice board of the office of the University in addition to the Internet. The result when published shall simultaneously be communicated to the institutions concerned.
18. The remuneration of the Examiners, Superintendents, Assistant Superintendents, Invigilators, Tabulators and collators and the deductions to be made in the remuneration for errors noticed shall be such as prescribed from time to time by the Board Management.
19. Where a student applies for revaluation, the answer books of the subjects in which the revaluation is sought will be sent to an examiner other than the one who evaluated it initially. The examiner so appointed will check and evaluate only those questions, which have been left unmarked. He will also check the total. The answer book will not be re-evaluated for already evaluated questions.
20. No ex-student candidate shall be admitted to an examination of the University unless he submits with his application the following
 - (i) The statement of marks (in original) obtained by him as a regular candidate at the said examination issued by the University together with an attested copy thereof, or
 - (ii) In case he was duly admitted to the said examination as a regular candidate but he could not appear thereat, a certificate from the institute last attended by him showing the year, the roll number and the examination to which he was admitted as a regular candidate.
21. No Candidate shall appear, in more than one-degree examination or in more than one subject for the Master's degree in one and the same year.
22. A candidate who has passed first year of Bachelor's degree, examination or Master's degree examination of another University/ Awarding Body (Indian or

Foreign) may be admitted to the next higher examination of the University for the corresponding degree subject to such conditions as laid down by the Academic Council from time to time on the credit transfers.

Provided at least 75% of the courseware offered by the University/ Awarding Body of the candidate match with the courseware of the University for the award of the corresponding degree.

23. No person who has been expelled or rusticated from any college or University or has been debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the sentence is in operation.

24. An application for admission to an examination received by the Controller of Examination after the last date notified by the University but not later than fifteen days after such last date may be entertained on payment of a late fee as prescribed from time to time.

25. Notwithstanding anything contained in the Ordinance relating to admission of candidates to an examination of the University, the Vice-Chancellor may, in special cases in which he is satisfied that the delay in submitting the application for admission to an examination is not due to lack or negligence on the part of the candidate and that it would be a great hardship to the candidate if his application is rejected, allow an application which is otherwise complete in all respects to be entertained with the late fee prescribed by the Board of Management from time to time even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in the foregoing paragraph.

26. (1) The controller of Examination shall issue an admission card in favour of a candidates if :-

- a) The application of the candidate is complete in all respects.
- b) The fees as prescribed have been paid by the candidate.
- c) The assignments have been submitted.
- d) The attendance is more than 60%.
- e) The student has scored a minimum of 50% marks in assignments and examinations collectively.

(2) Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination until he is issued an admission card for appearing in the examination.

- (3) The admission card issued in favour of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that :-
- a) The admission card was issued by mistake, or the candidate was not eligible to appear in the examination.
 - b) Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in or with the application for enrolment, admission to the institute, college or school are false or incorrect.
- (4) The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, grant a duplicate admission card on the payment of a fee prescribed. Such a card shall show in a prominent place the word "Duplicate".
27. (1) A candidate who due to sickness or other cause is unable to present himself/herself at an examination, shall not receive a refund of his fee.

Provided that the Vice-Chancellor may, in case in which he is satisfied about the genuineness or merit of it, order for adjustment of the following portion of the fee towards the next immediate examination viz.

- i. Examination fee after deduction of 10% fee paid.
- ii. Fee for statement of marks.

Other fees paid by the candidate shall lapse to the University. Application for such adjustment from a candidate accompanied by a Medical Certificate of illness, if applicable, must be sent so as to reach the Controller of Examination not later than 30 days from the date of commencement of the examination at which the candidate was to appear.

- (2) The examination fees paid by a regular candidate who is debarred from appearing at an examination due to shortage in attendance at lectures/particulars, may be refunded after deduction of service charges of 10%.
- (3) The examination and other fees of a candidate whose application for appearing at an examination has been rejected for some reason or he could not furnish his form within the prescribed date; necessary fees having been

paid in the University account, may be refunded after deduction of service charges of 10%.

- (4) The examination and marks statement fee of a candidate who dies before appearing at the examination may be refunded in full to his guardian or his successor.
 - (5) The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an examination is cancelled on account of producing fraudulent documents or giving false particulars shall stand forfeited.
28. (1) Any candidate, who has appeared at an examination conducted by the University, may apply to the Controller of Examination for the scrutiny of his marks in the answer scripts of theory papers in any subject and rechecking of his results. Such application must be made so as to reach the Controller of examination within 15 days of the publication of the result of the examination.
- (2) Such application must be accompanied by fee as per schedule given below --
- | | | |
|-----|----------------|------------|
| (a) | In one subject | Rs. 200/- |
| (b) | In all subject | Rs. 1000/- |
- (3) A candidate shall not be entitled to a refund of the fee.
 - (4) The result of scrutiny shall be communicated to the candidate.
 - (5) If as a result of scrutiny, it is found that the examination should be declared as having passed or placed in a higher division, the result of the candidate shall be revised accordingly.
29. Duplicate copies of the following certificate shall be granted on payment of the fee mentioned against each viz.
- | | | |
|-------|-------------------------|------------|
| (i) | Statement of Marks | Rs. 500/- |
| (ii) | Migration certificate | Rs. 500/- |
| (iii) | Provisional Certificate | Rs. 500/- |
| (iv) | Degree Certificate | Rs. 1500/- |

Provided further, the duplicate copy of the Migration Certificate, Degree, Diploma shall not be granted except in cases in which the Vice-Chancellor is satisfied by the production of an affidavit on a stamped paper or proper value required by law for the time being in force that the applicant has not utilized the original documents for appearing at an examination and has lost the same or that the same has been destroyed and that the applicant really need a duplicate copy. Duplicate copy shall be issued only once.

30. The names of the first ten successful candidate in each final Degree Examination other than supplementary examination who obtain first division shall be declared in order of Merit.
31. Notwithstanding anything contained in the concerned ordinance and examinee who has appeared in all the theory papers, practicals, viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester examination in 1st attempt and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects in any of the Graduate examinations but secures more than the minimum aggregate marks required, may be given a grace of upto five marks with not more than three marks given in any one subject to enable him to pass the examination. These marks shall, however, not be counted towards the total.
32. The Vice-Chancellor may award one grace mark in case the candidate is missing a division by one mark. Where the deficiency is so condoned one mark shall not be added to the total.
- 33.(1) The following shall be eligible to appear at supplementary examination.
 - (a) Candidates who have failed at any Bachelors/ Masters examination in not more than two subjects.
 - (b) Candidate for examination other than those enumerated in (a) above who are declared eligible to appear at a supplementary examination in accordance with the provisions of the examination in accordance with the provisions of the respective examination Ordinance.
- (2) In the case of subject for supplementary examination on which there is also a practical test, a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical and in practical only if he has passes in the written papers. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both the parts of the subject.
- (3) Except when provided otherwise in the Ordinance concerned a candidate who has been declared eligible for a supplementary examination may appear as supplementary examination candidate in the two examinations immediately following the examination in

which he was declared to be so eligible and thereafter he shall be required to appear in all the papers at the next examination.

- (4) A candidate appearing in the supplementary examination shall be declared to have passed the examination if he secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be except when provided otherwise in the examination Ordinance concerned. The marks obtained by the candidate in the supplementary/examination shall taken into account in determining the division at the examination.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

क्रमांक एफ 1-176/2003/38.—कुलाधिपति, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक-392/11-15-2/2003, दिनांक 5-12-2003 के द्वारा डॉ. सुनील कुमार वर्मा, प्राध्यापक, गणित, शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए कुल सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में डॉ. सुनील कुमार वर्मा, प्राध्यापक, गणित, शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर की सेवायें उक्त विश्वविद्यालय को ली जाने लगे हुए उक्त पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2004

क्रमांक 02/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (एक) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	काण्डकेला	2.529	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोटरी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग दिनांक 14 जनवरी 2004

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153	0.07
154	0.01

क्रमांक 01/अ-82, 2002-2003/भू-अर्जन/04. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बालोद

(ग) नगर/ग्राम-मुल्लेगुड़ा (हरठिमा), प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

योग	2	0.08
-----	---	------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—
आदमोबाद-घोठिया-डौण्डी के कि.मो. 12/10 पर निर्माणाधीन
सूखा नाला पर पुल एवं पहुंचमार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद के कार्यालय में किया
जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

